MASIK PATRIKA

JANUARY
2025

WESTERN U.P. CHAMBER OF COMMERCE AND INDUSTRY

"CHAMBER BHAWAN" BOMBAY BAZAR, MEERUT CANTT-250001 (U.P.) INDIA

Phone No : (0121)2661238, 2661177
Fax : 0121-2661685
E-mail : wupcc@rediffmail.com
Website : www.wupcc.org

व्यापार एवं उद्योग की समृद्धि के लिये

- **Patron**

Dr. Mahendra Kumar Modi

- **President**

Dr. Ram Kumar Gupta

- **Sr. Vice President**

Shri G.C. Sharma

- **Jr. Vice President**

Shri Neel Kamal Puri, Muzaffarnagar

- **Secretary / Editor**

Smt Sarita Agarwal

Patrika Committee

- **Chairman**

Shri Rahul Das

- **Co-Chairman**

Shri Sushil Jain

- **Members**

Shri Manoj Kumar Gupta (Hapur)
Shri Rakesh Kohli
Shri Trilok Anand
Shri Rajendra Singh
Shri Atul Bhushan Gupta

- **Co-Editor**

Ms. Rekha Yadav

INDEX

- निवेश मित्र पोर्टल से बैंकिंग लेनदेन पर नहीं लगेगा शुल्क
- आरटीजीएस और एनईएफटी मे दिखेगा खाताधारक का नाम
- क्यूआर कोड वाला पैन ई– मेल पर मुफ्त पाएं
- मेरठ में सूरज की किरणों से बन रही है बिजली
- अफसरों की जिम्मेदारी तय केस्कोकी तर्ज पर होगा काम
- उत्तर प्रदेश में बनेगी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क

- RBI's New Guidelines: Bank Account Closures Begin January 1, 2025

Uttar Pradesh earmarks 17,000 acres for multimodal logistics parks

- India's automobile industry set to become global leader in 5 Years: Nitin Gadkari
- UP govt's new export policy to provide additional benefits to exporter
- Centre to launch new credit guarantee scheme for MSME sector up to Rs 100 cr
- Uttar Pradesh govt plans e-commerce booster shot for the MSME sector
- Nipro Pharma Packaging is now Great Place to Work certified!!

निवेश मित्र पोर्टल से बैंकिंग लेनदेन पर नहीं लगेगा शुल्क

निवेश और व्यापार सुविधा को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार की पहल निवेश मित्र पोर्टल में बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। सभी बैंक जल्द ही निवेश मित्र पोर्टल बैंकिंग गेटवे लेनदेन पर कोई शुल्क नहीं लेंगे। ये सुविधा एक जनवरी से मिलेगी।

भारत के सबसे बड़े सिंगल विंडो पोर्टल में से एक, निवेश मित्र 42 विभागों की 500 से अधिक ऑनलाइन सेवाएं दे रहा है।

निवेश मित्र के सुचारू संचालन के लिए नोडल एजेंसी इंवेस्ट यूपी पोर्टल के पेमेंट गेटवे विकल्पों का विस्तार कर रही है। वर्तमान में आईसीआईसीआई बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और एचडीएफसी बैंक पेमेंट गेटवे के रूप में सूचीबद्ध थे जो डेबिट कार्ड, यूपीआई, इंटरनेट बैंकिंग और क्रेडिट कार्ड से भुगतान का विकल्प दे रहे थे। अब कुल 11 बैंक पेमेंट गेटवे की सुविधा देंगे।

आरटीजीएस और एनईएफटी मे दिखेगा खाताधारक का नाम

जल्द ही ऑनलाइन फंड ट्रांसफर सिस्टम जैसे आरटीजीएस और एनईएफटी के लिए जिस ग्राहक को राशि ट्रांसफर होगी, उसका नाम दिखेगा। इससे लेन–देन में गलतियों या धोखाधड़ी से बच सकेंगे। आरबीआई ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया से कहा है, वह ऐसी सुविधा विकसित कर सभी बैंकों को इसमें शामिल करे। रिजर्व बैंक ने बताया, सभी बैंक जो रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (आरटीजीएस) और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर (एनईएफटी) सिस्टम के सदस्य हैं, उन्हें एक अप्रैल से पहले यह सुविधा मुफ्त देनी होगी। फिलहाल यूपीआई व तत्काल भुगतान सेवा (आईएमपीएस) में यह सुविधा मिलती है।

एनपीसीआई इससे जुड़ें किसी डाटा को संग्रहित नहीं करेगा। जो बैंक आरटीजीएस और एनईएफटी सिस्टम के भागीदार हैं, वे अपने ग्राहकों को इंटेरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से यह सुविधा उपलब्ध कराएंगे।

क्यूआर कोड वाला पैन ई–मेल पर मुफ्त पाएं

केंद्र सरकार ने पैन कार्ड को अधिक सुरक्षित बनाते हुए इसमें क्यूआर कोड की सुविधा प्रदान की है। इस कदम का उद्देश्य डिजिटल सत्यापन को आसान और तेज बनाना है। क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड तकनीकी रूप से अधिक उन्नत है, जिस पर छपे क्यूआर कोड में कार्ड धारक की व्यक्तिगत जानकारी को एन्क्रिप्ट किया गया होता है यानी किसी के लिए भी इस जानकारी को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। इस तकनीक के जरिए, कार्ड की प्रामाणिकता की पुष्टि कुछ ही सेकंड में की जा सकती है।

वित्तीय लेनदेन से लेकर दूसरे जरूरी कामों में पैन कार्ड का इस्तेमाल जरूरी होता है। अब केंद्र सरकार ने इसके प्रारूप में बदलाव कर दिया है। इसके तहत अब पैन 2.0 नए और अपग्रेडेट क्यूआर कोड के साथ दिखेगा। यह डिजिटल प्रारूप में उपलब्ध होगा। नए पैन कार्ड में सुरक्षा फीचर्स और कई तकनीकी सुधार किए गए हैं। इसमें कार्ड धारक का नाम और पैन नंबर शामिल होगा, जिसे स्कैन करके तुरंत सत्यापन हो जाएगा।

क्यूआर कोड वाला पैन कार्ड एम आधार या ई–आध. ार सिस्टम जैसा होगा। वर्तमान में जो पैन कार्ड है वह केवाईसी में काम तो आता है, लेकिन यह किसी भी रूप में पते के प्रमाण के रूप में काम नहीं करता है, जबकि नया पैन कार्ड इन सभी उद्देश्यों के लिए मान्य होगा। इसके अलावा इस बार से पैन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे टैक्स जमा करने वालों की पहचान सही ढंग से की जा सकेगी।

क्यूआर कोड एक टेक्नोलॉजी इनोवेशन है, जो जानकारी को बारकोड के रूप में अपने अंदर करता है। इस जानकारी को एन्क्रिप्टेड (गोपनीय) रखता है, जिससे किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ की संभावना कम हो जाती है। पैन कार्ड में क्यूआर कोड जोड़ने से उपयोगकर्ता की जानकारी अधिक सुरक्षित हो जाती है। पैन 2.0 योजना में क्यूआर कोड डाइनैमिक सुविधा से लैस होगा जिससे पैन डेटाबेस में मौजूद लेटेस्ट डेटा भी देखे जा सकेंगे। इनमें फोटो, सिग्ने. चर, नाम, माता–पिता के नाम और जन्मतिथि की जानकारी शामिल है।

एक ही पैन से सारे काम होंग

जानकारों का कहना है कि आने वाले समय में पैन 2.0 एक यूनिवर्सल पहचान संख्या बन जाएगा। यह कई सेवाओं के लिए आवश्यक अलग अलग काड़ों को खत्म करेगा। इससे करदाता और कारोबारियों को लाभ मिलेगा। पैन जीएसटी दाखिल करने, कॉरपोरेट पंजीकरण और कर से संबंधित कई प्रकार की सेवाओं में एक प्रमुख आईडी कार्ड की भूमिका निभाएगा। साथ ही यह व्यवसाय में कर कटौती और ऊ।छ (टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर) जैसे पहचान पत्रों की मांग को खत्म करके इन सेवाओं को और सरल बनाएगा।

कौन जारी करेगा नया कार्ड

भारत में दो संस्थाओं पैन कार्ड जारी कर सकती हैं– 1. प्रोटियन ई–गवर्नेंस (पहले NSDL), और 2. UTI इन्फ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज लिमिटेड (UTIITSL)। पैन कार्ड के पीछे दी गई जानकारी से यह पता लगाया जा सकता है कि आपका कार्ड किसने जारी किया है। इस जानकारी के आधार पर आपको संबंधित वेबसाइट पर जाकर अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। ई–मेल पर मांगने के लिए आवेदन करने के 24 घंटे के भीतर नया पैन कार्ड डाउनलोड करने का विकल्प मिल जाता है।

एक से अधिक पैन कार्ड नहीं रख सकते

आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के मुताबिक, किसी भी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड रखने की अनुमति नहीं है। अगर किसी व्यक्ति के पास दो पैन है तो वह जल्द से जल्द अपने पैन को सरेंडर करा लें। वरना इसके लिए आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। ऐसे में, अगर किसी व्यक्ति के पास एक से अधिक पैन कार्ड है, तो आयकर अधि. नियम की धारा 272बी के अनुसार उनपर 10,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। आपको बता दें कि पैन 2.0 प्रोजेक्ट में एक व्यक्ति के एक से अधिक पैन रखने की घटनाएं कम हो सकती हैं

प्लास्टिक कार्ड के लिए शुल्क देना होगा

जिसके पास पहले से पैन कार्ड है, वे इसे अपडेट करा सकते हैं। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ई मेल पर ई–पैन मंगाने के लिए कार्डधा. रक होल्डर को किसी तरह का शुल्क नहीं देना होगा। हालांकि प्लास्टिक कार्ड के प्रारूप में मंगाने के लिए आवेदक को 50 रुपये का निर्धारित शुल्क देना होगा। वहीं, भारत से बाहर पैन कार्ड की डिलीवरी के लिए आवेदक को अतिरिक्त शुल्क देना होगा। आयकर विभाग के डेटाबेस में आपका ईमेल होना चाहिए। अगर नहीं है तब करदाता पैन 2.0 के तहत आयकर विभाग के रिकॉर्ड में ईमेल पते को निशुल्क अपडेट कर सकते हैं।

पैन सरेंडर करने की प्रक्रिया

पैन सर्विस वेबसाइट protean के मुताबिक, अतिरिक्त पैन कार्ड को सरेंडर करवाने के लिए आपको आयकर विभाग के समक्ष पैन बदलने का आवेदन देना होगा। इसके साथ आपको वर्तमान पैन नंबर का भी जिक्र करना होगा। इसके अलावा, आपको अनजाने में दिए गए अन्य सभी पैन का नंबर भी बताना होगा। इस फॉर्म के साथ आपको सरेंडर के लिए फॉर्म 11 जमा करना होगा। साथ में, संबंधित सारे पैन कार्ड की एक–एक कॉपी भी जमा करनी होगी।

SUBHAM ORGANICS LIMITED
Mfrs. of
PHARMACEUTICALS INDUSTRIAL CHEMICALS, BULK DRUGS & DRUG INTERMEDIATES

Corporate Office & Works:
303-A, Industrial Area,
Partapur Meerut- 250103
(U.P.) India Ph. : 91-121-2440711
Email: lionramkumar@gmail.com

Regd Office:
204, M.J. Shopping Centre,
3, Veer Savarkar Block,
Shakarpur, Delhi-110092
Ph.: 91-11-22217636

ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया

1. NSDL (www.onlineservices.nsdl.com) या यूटीआई. टीएसएल (www.pan.utiitsl.com/reprint.html) की वेबसा. इट पर जाएं। अगर आप नया पैन कार्ड बनवा रहे हैं, तो New PAN Applicationll पर क्लिक करें।

2. यदि आपके पास पहले से पैन कार्ड है और आप इसे क्यूआर कोड के साथ अपडेट करवाना चाहते हैं, तो Reprint PAN Card का विकल्प चुनें।

3. इसके बाद अपना जरूरी जानकारी दर्ज करें, जैसे पैन, आधार (केवल व्यक्तियों के लिए) और जन्म तिथि। आवश्यक टिक बॉक्स चुनें और श्सबमिटश पर क्लिक करें।

4. फिर आपकी स्क्रीन पर एक नया वेबपेज खुलेगा, जहां आपको आयकर विभाग के साथ अपडेट किए गए वर्तमान विवरणों की जांच करनी होगी। इसके बाद आपको वन–टाइम पासवर्ड (ओटीपी) का विकल्प आएगा।

5. आप मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और दोनों पर ओटीपी प्राप्त कर सकते हैं। आयकर विभाग के रिकॉर्ड में उपलब्ध संचार पते पर भेजे जाने वाले पैन कार्ड के लिए टिक बॉक्स चुनें। फिर श्जनरेट ओटीपीश पर क्लिक करें।

6. मोबाइल या ईमेल जिस विकल्प का आप चयन करेंगे, उस पर आपको ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी केवल 10 मिनट के लिए वैध होगा। इसे सत्यापित करें।

7. इसके बाद भुगतान का विकल्प आएगा। अगर ईमेल पर कार्ड मंगाना है तो कोई शुल्क नहीं देना होगा। वहीं प्लास्टिक कार्ड के लिए 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

8. फिर श्मैं सेवा की शर्तों से सहमत हूँ पर टिक बॉक्स चुनना होगा और सचमिट पर क्लिक करना होगा। एक नया वेबपेज खुलेगा, जहां आपको 50 रुपये का भुगतान करना होगा।

9. भुगतान हो जाने के बाद एक रसीद मिलेगी। इसके बाद आप 24 घंटे बाद एनएसडीएल की वेबसाइट से ई–पैन डाउनलोड कर सकेंगे। फिजिकल पैन कार्ड 15– 20 दिनों के भीतर आपके पते पर भेज दिया जाएगा।

ऑफलाइन आवेदन प्रक्रिया

1. फॉर्म प्राप्त करें: नजदीकी एनएसडीएल, यूटीआई. आईटीएसएल कार्यालय या अधिकृत पैन सेवा केंद्र से आवेदन फॉर्म प्राप्त करें।

2. फॉर्म भरे: अपनी व्यक्तिगत जानकारी को सावध. ानीपूर्वक भरें। पहचान प्रमाण, पता प्रमाण, और जन्म प्रमाणपत्र के साथ फॉर्म जमा करें।

3. शुल्क जमा करें: शुल्क का भुगतान नकद, ड्राफ्ट, या चेक के माध्यम से करें। भरे हुए फॉर्म को संबंधित कार्यालय में जमा करें।

4. पैन कार्ड प्राप्त करें: पंजीकरण प्रक्रिया पूरी होने के बाद आपका नया पैन कार्ड आपको डाक द्वारा भेजा जाएगा।

इन बातो का भी रखे ध्यान

1. यह पैन कार्ड डिजिटल है यानी यह पेपर लेस्स कार्ड है। इस कार्ड मे क्यू आर कद है द्य इस क्यू आर कद के माध्यम से पेन होल्डर की जानकारी पाई जा सकती हैद्य इस कार्ड मे सभी जानकारी पूरी तरह एन्क्रिप्टेड होगी।

2. इस कार्ड के लिए आप को 15 दिनों का इन्तजार नहीं करना होगा। आवेदन के करीब 30 मिनट में आपके मेल –आई डी पर पैन कार्ड आ जायेगा।

3. जिस के पास पुराना पैन कार्ड है, उन्हें दुबारा बनवाने की जरूरत नहीं है। वह अपनी सुविधा के अनुसार नई ई – पेन कार्ड या फिजिकल कार्ड ले सकते है। मौजूदा पैन कार्ड भी वैलिड रहेंगे है।

4. नई पैन से बायोमेट्रिक और आधार इंटिग्रेशन से पहचान की चोरी और पैन का गलत इस्तेमाल रोका जा सकेगा। पैन 2.0 से टैक्स फाइलिंग आसान हो जाएगी है।

5. सबसे पहले आपको चेक करना होगा की आपका पैन आधार से लिंक हे या नहीं। अगर आपने अभी पैन को आधार से लिंक नहीं किया हे, तो आपको 1000 रूपये का जुर्मना देना पड़ेगा।

मेरठ में सूरज की किरणों से बन रही बिजली

मेरठ और बागपत जिलों में लोग सौर ऊर्जा की तरफ आकर्षित हो रहे है। हजारों लोगों के मकानों की छतों पर सूरज की किरणों से बिजली बन रही है। पीएम सूर्य घर मुक्त बिजली योजना भी परवान चढ़ रही है। आम लोगों को नहीं बल्कि किसान भी सोलर प्लांट लगाकर बिजली पैदा करने लगे। अब किसान बिजली बेचने वाले बन जाएंगे।

मेरठ और बागपत जिलों की बात करे तो बिजली की बर्बादी रोकने के साथ ही सूर्य की किरणों से बिजली बनाकर करीब 50 मेगावाट से अधिक बिजली के लिए पावर कारपोरेशन से निर्भरता कम कर ली। पावर कारपोरेशन के अफसरों की माने तो पश्चिमांचल में सात लाख 25 हजार लोगों के घरों पर सूरज की किरणों से बिजली बनेगी तो पश्चिमांचल डिस्कॉम में करीब 300 से 400 मेगावाट बिजली की खपत कम हो जाएगी।

सोलर सिटी बनेगा मेरठ

- पश्चिमांचल के 14 जिलों में सात लाख 25 हजार घरेलू परिसरों में सोलर रूफटॉप लगेंगे।
- पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत लोगो को सौर ऊर्जा के लिए प्रेरित कर रहे।

इन योजनाओं से मिल रहा बढ़ावा

- प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना
- प्रधानमंत्री कुसुम सी– 1 और सी– 2 योजना
- सूर्य मित्र प्रशिक्षण कार्यक्रम
- पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना की स्थिति
- 14 जिलों में सात लाख 25 हजार लोगों के घरों पर बनेगी सूरज की किरणों से बिजली

अफसरों की जिम्मेदारी तय केस्कोकी तर्ज पर होगा काम

कानपुर में केस्को के बाद काम आधारित अफसरों की जिम्मेदारी वाली बिजली व्यवस्था लागू करने में प्रदेश में मेरठ दूसरा शहर बन गया है। शहर के पांच डिवीजन खत्म करते हुए शहर को दो भागों मेरठ साउथ और नॉर्थ में बांटा गया है। छह अधिशासी अभियंता अलग–अलग कार्यों के साथ शहर की बिजली आपूर्ति और उपभोक्ताओं की समस्याओं के समाधान के साथ विभागीय योजनाओं के क्रियान्वयन का काम संभालेंगे। मेरठ शहर में बिजली की नई व्यवस्था नौ दिसंबर से लागू हो गई है, जबकि 15 दिसंबर से बरेली और अलीगढ़ में भी इसी तर्ज पर बिजली व्यवस्था लागू होगी। मेरठ में नई व्यवस्था के लिए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग कराते हुए तैनाती देने के साथ निर्देशित कर दिया। एमडी पीवीवीएनएल ईशा दुहन ने इस बारे में जानक. ारी दी।

ऐसे तय किया कार्य: छह अधिशासी अभियंताओं की अलग–अलग जिम्मेदारी तय करते हुए तैनाती दी गई है। इनमें एक एक्सईएन 33केवी लाइन और उपेकेंद्रों को देखेंगे, दूसरे एक्सईएन 11केवी एवं एलटी लाइन (मेरठ नार्थ) का कार्य देखेंगे। दोनों के ऑफिस यूनिवर्सिटी रोड पर होंगे। तीसरे मेरठ साउथ में एक्सईएन माधवपुरम में बैठेंगे और वह 11केवी लाइन और एलटी लाइन का कार्य देखेंगे। कॉमर्शियल–1 और कॉमर्शियल–2 एक्सईएन के ऑफिस साकेत कुंज में होंगे। कॉमर्शियल–1 मीटर, बिलिंग, मीटर टेस्टिंग, राजस्व वसूली आदि के कार्य देखेंगे। कॉमर्शियल–2 एक्सईएन कनेक्शन संबंधित सभी मामले, एमआरआई डाटा, एनर्जी एकाउंटिंग, पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना आदि कार्य देखेंगे। रेड और एडिमन एक्सईएन का कार्यालय विक्टोरिया पार्क में होगा, वह बिजली चोरी रोकने को छापेमारी से लेकर 1912 हेल्पलाइन, आईजीआरएस, पब्लिक रिलेशन, बैठकों के नोडल अफसर, कोर्ट केस, सोशल मीडिया मैनेजर आदि का कार्य संभालेंगे। शहर नार्थ क्षेत्र का ऑफिस यूनिवर्सिटी होगा और अधिशासी अभियंता विपिन कुमार सिंह होंगे। मेरठ साउथ में अधिशासी अभियंता विनोद कुमार वर्मा होंगे।

उत्तर प्रदेश में बनेगी मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क

उत्तर प्रदेश में अब मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्कों (एमएमएलपी) का भी निर्माण किया जा सकेगा। इस संबंध में कैबिनेट की बैठक में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति–2024 को स्वीकृति प्रदान कर दी गई है।

एमएमएलपी में 1,000 करोड़ रुपये के न्यूनतम निवेश के साथ 100 करोड़ रुपये तक का विदेशी निवेश भी किया जा सकेगा। सरकार भूमि खरीद पर निवेशकों को 30 प्रतिशत तक की छूट भी प्रदान करेगी। निवेश के लिए फॉर्च्यून ग्लोबल 500 अथवा फॉर्च्यून इंडिया 500 में सूचीबद्ध कंपनियों के ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।

मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क नीति के तहत आवेदन करने वाली इकाई को प्रति एकड़ 10 करोड़ रुपये का न्यूनतम निवेश करना होगा। औद्योगिक विकास प्राधिकरण भूमि की वर्तमान दर में अपने स्तर से 30 प्रतिशत लागत कम करके भूमि आवंटित करेंगे। नीति में स्पष्ट किया गया है कि पात्र निवेश की अवधि तक भूमि संबंधित प्राधिकरण के पास बंधक रहेगी। अनुमन्य समय में परियोजना के पूरा होने के बाद भूमि बंधन मुक्त कर दी जाएगी। अगर आवेदक निवेश अवधि के भीतर संचालन करने में विफल रहते हैं तो भूमि पर दी गई छूट को 12 प्रतिशत ब्याज की दर से वसूला जाएगा।

अमेरिका, यूरोपियन यूनियन, चीन, रूस, ब्राजील व यूनाइटेड अरब अमीरात की नीति का अध्ययन करके बनाई गई उत्तर प्रदेश की नीति के लिए इन्वेस्ट यूपी को नोडल संस्था बनाया गया है। एमएमएलपी एक्सप्रेसवे व हाईवे से जुड़े बड़े शहरों में ही बनाए जाएंगे। साथ ही औद्योगिक विकास प्राधिकरण या राज्य सरकार की किसी संस्था से पट्टे पर ली गई भूमि पर 100 प्रतिशत की दर से स्टांप ड्यूटी में छूट प्रदान की जाएगी। यह छूट राज्य सरकार की संबंधित संस्था के प्रमुख के पक्ष में छूट की समतुल्य राशि की बैंक गारंटी प्रस्तुत करने पर प्रदान की जाएगी। लॉजिस्टिक्स पार्कों के लिए 17,000 एकड़ की भूमि विभिन्न हिस्सों में चिह्नित की जा चुकी है।

आयुष्मान योजना के लिए श्रमिकों को पंजीकरण शुल्क में छूट

कैबिनेट की बैठक में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण शुल्क में छूट देने संबंधी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी तक असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को आयुष्मान योजना का लाभ लेने के लिए पंजीकरण शुल्क का भुगतान करना पड़ता था।

RBI's New Guidelines: Bank Account Closures Begin January 1, 2025

- RBI's new guidelines will close dormant, inactive, and zero balance accounts starting January 1, 2025.
- Account holders must take steps to reactivate or maintain their accounts to avoid closure.
- Reactivate inactive accounts by making transactions and engaging with dormant accounts at the bank branch.
- Zero balance accounts will be closed to prevent misuse and enhance KYC compliance.
- New FD rules with NBFCs and HFCs will simplify premature withdrawals and communication.

The Reserve Bank of India (RBI) has announced new regulations that will lead to the closure of certain types of bank accounts starting January 1, 2025. This initiative aims to improve banking security, reduce fraud, and enhance operational efficiency. The accounts affected by these guidelines include dormant accounts, inactive accounts, and zero balance accounts. Here's what you need to know:

Types of Accounts Facing Closure

1. Dormant Accounts: Accounts that have not shown any transaction for two or more years will be classified as dormant. These accounts are more susceptible to misuse and fraud, making their closure essential for maintaining banking security.

2. Inactive Accounts: If an account has had no transactions for over 12 months, it will be considered inactive. To prevent closure, account holders must reactivate the account by making at least one transaction.

3. Zero Balance Accounts: Accounts that have been maintaining a zero balance for an extended period may also be closed. This step is intended to eliminate the misuse of such accounts and ensure compliance with Know Your Customer (KYC) norms.

Steps to Avoid Account Closure

To ensure your account remains active and open, customers are advised to take the following actions:

• Reactivate Inactive Accounts: If your account has been inactive for over 12 months, make a transaction to reactivate it.

• Engage with Dormant Accounts: Accounts that have been dormant for two years should be reactivated by visiting the bank branch.

• Maintain a Positive Balance: Avoid leaving your account with a zero balance for long periods to keep it active.

Along with the account closures, RBI has introduced new rules for fixed deposits (FDs) with Non-Banking Financial Companies (NBFCs) and Housing Finance Companies (HFCs). The new regulations simplify terms for premature withdrawal and aim to improve communication between financial institutions and depositors.

VK TYRE INDIA LIMITED

MANUFACTURERS & EXPORTERS OF:

AUTOMOBILE & AGRICULTURE TYRES

Sybly Industrial Area, Pawanpuri,
Muradnagar-201206
MOB. No: 9568129777,7900200100

Website: www.vktyre.com

TIRE TRACKS

-vector illustration-

Email: info@vktyre.com

Uttar Pradesh earmarks 17,000 acres for multimodal logistics parks

The Uttar Pradesh government has earmarked 17,000 acres for developing multimodal logistics parks (MMLPs) across the state to feed its ambitious $1 trillion economy mission.

The state government is looking to offer a 30 per cent subsidy on land cost provided the company invests at least Rs 1,000 crore in such a project.

An MMLP integrates multiple transportation modes with warehousing and distribution at a single location. It fosters supply chain efficiency and reduces transportation costs.

The nodal agency, UP Expressway Industrial Development Authority (UPEIDA), has identified swathes of land for MMLP projects in the vicinity of expressways and major highways near big cities.

"The state industrial development department has also drafted a UP Multimodal Logistics Park Policy 2024, which will soon be tabled before the state cabinet for approval," a government official said.

The proposed policy will provide an array of incentives and sops to the private companies on land and capital investment.

Leading domestic and international players, including from the US and the Gulf, have evinced interest in setting up MMLPs due to the growing network of expressways, airports, urban centres, and tourist hotspots in UP. The interested companies include Sumitomo Corporation, Sembcorp, DP World, and Rank Logistics, the official said.

The proposed MMLPs will comprise modern warehouses, cold storage, intermodal cargo containers, and cargo terminals. It will provide relevant services such as customs clearance, storage yard, warehouse management, testing centre, packaging, grading, and labelling under one roof.

UP's first multimodal waterway terminal park is being developed on the banks of the Ganga in Varanasi, the parliamentary constituency of Prime Minister Narendra Modi.

The Yogi Adityanath government 2.0 is making big-ticket investments in roads and expressways to make the state a $1 trillion economy. The expanding road infrastructure coupled with a proliferating chain of airports and industrial clusters is fuelling the growth of other sectors such as housing, realty, hospitality, and commercial vehicles.

With substantial investments in infrastructure, including roads and expressways, UP is among the fastest growing markets in India, said Viplav Shah Light Commercial Vehicle (LCV) Business head of Ashok Leyland.
He said the state will continue to witness traction in the commercial vehicles segment owing to big infra projects.
Meanwhile, UPEIDA has partnered with Swiss company ETH Zurich's arm RTDT Laboratories AG to assess riding quality and comfort metrics of expressways in UP.

India's automobile industry set to become global leader in 5 Years: Nitin Gadkari

Union Minister for Road Transport and Highways Nitin Gadkari expressed confidence about India's automobile industry becoming the number one globally in the next five years.
Speaking at the Amazon Smbhav Summit on Tuesday, Gadkari highlighted the industry's impressive growth, noting it has surged from Rs 7 lakh crore to Rs 22 lakh crore since he assumed office.
"Currently, the USA leads with a market size of Rs 78 lakh crore, followed by China at Rs 47 lakh crore. India, now at Rs 22 lakh crore, has significant potential," Gadkari stated, adding, "I am confident that within 5 years, India will be the number one automobile market in the world."
The minister pointed to the presence of leading global automobile brands in India as a clear sign of the country's growing stature in the industry. He also outlined his ministry's ambitious plans to enhance India's logistics infrastructure, aiming to cut logistics costs to 9 per cent within the next two years.
"Logistics costs in India currently stand at 16 per cent, while in China it is 8 per cent, and in the USA and Europe, it is around 12 per cent. The government has set a target to reduce logistics costs, and within 2 years, we aim to bring it down to 9 per cent," Gadkari said.
Gadkari also highlighted several infrastructure projects that will drastically reduce travel times between major cities. For instance, the journey from Delhi to Dehradun, which currently takes about nine hours, will be reduced to just two hours by January 2025.
Similarly, travel times between Delhi and Mumbai, as well as Chennai and Bengaluru, are expected to see significant reductions in the near future.
In his speech, the minister emphasized the importance of adopting alternative fuels and biofuels in the country's transportation sector. He explained that using bio-ethanol in vehicles could not only reduce fuel costs but also help lower pollution levels.
Gadkari also unveiled plans to convert organic waste into hydrogen fuel and other valuable resources using advanced recycling technologies. Highlighting the substantial municipal waste generated in Delhi, he said, "Currently, only 80 lakh tons of waste are utilized. Our vision is to convert organic waste into hydrogen. By segregating waste, we can extract petrol, plastic, metals, and glass, which can all be recycled. Additionally, we have technology that can convert waste into green hydrogen."
Gadkari's remarks underline the government's commitment to transforming India's transportation and logistics sectors, positioning the country as a global leader in both the automobile industry and sustainable energy initiatives.

UP govt's export policy to provide additional benefits to exporters

The Uttar Pradesh government is drafting a new export policy to boost the state's share in India's exports. The move aims to provide additional incentives to exporters.
In the last financial year (FY24), UP's merchandise exports were worth nearly $20.67 billion, contributing 4.71 per cent to India's total exports. With the new policy, the government targets to increase this share to 7.5 per cent, a senior official said. For the first six months of FY25, the state logged exports worth $10.56 billion, raising its share in the country's total exports to 4.89 per cent.
The proposed policy would introduce several incentives for exporters, especially in the food processing, handicrafts, and One District One Product sectors. UP is known for its traditional industries, such as Banarasi silk sarees, carpets from Bhadohi, chikan embroidery from Lucknow, Kanpur's leather goods, and leather footwear from Agra.
The policy would emphasise job creation and offer incentives, including marketing development support, air freight subsidies, international certification subsidies, and gateway port freight subsidies, the official added
The state government is aiming to achieve merchandise exports worth Rs 3 trillion in the next two to three years. Being a landlocked state, UP

is also focusing on creating infrastructure to support its export supply chain.

The state plans to develop all 75 districts into potential export hubs by building a robust network of warehouses, cargo terminals, and trucking hubs. These facilities will be located in industrial zones and near expressway projects.

Centre to launch new credit guarantee scheme for MSME sector up to Rs 100 cr

NEW DELHI: Financial Services Secretary M Nagaraju said the government would soon launch a new credit guarantee scheme for the MSME sector covering loans up to Rs 100 crore.

"We are likely to come up with a scheme, which was announced by Finance Minister in her last Budget, that could provide loans up to Rs 100 crore without guarantee, if they are already having the enterprise," he said.

The scheme is expected to be placed before the Union Cabinet soon for its approval.

"For facilitating term loans to MSMEs for purchase of machinery and equipment without collateral or third-party guarantee, a credit guarantee scheme will be introduced. The scheme will operate on pooling of credit risks of such MSMEs. A separately constituted self-financing guarantee fund will provide, to each applicant, guarantee cover up to Rs 100 crore, while the loan amount may be larger," the Finance Minister Nirmala Sitharaman had announced in Budget 2024-25.

The borrower will have to provide an upfront guarantee fee and an annual guarantee fee on the reducing loan balance, she had said.

Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs) sector employs 50 million people, he said.

MSMEs exports have witnessed a remarkable rise,

increasing from Rs 3.95 lakh crore in 2020-21 to Rs 12.39 lakh crore in 2024-25, underscoring their critical role in boosting India's economy and strengthening global trade.

The MSME sector in India has consistently demonstrated remarkable resilience and adaptability, significantly contributing to the nation's GDP over the years.

The Gross Value Added (GVA) by MSMEs in India's GDP was 29.7 percent in 2017-18, rising to 30.1 percent in both 2022-23.

To promote entrepreneurship in rural India, Nagaraju said, the government is very keen to lend more to rural areas through its various schemes.

As the country surges ahead, he said, there is need to focus on four things, quality, linkages for exports, capacity building, and support to achieve the vision of Vikshit Bharat.To promote entrepreneurship in rural India, Nagaraju said, the government is very keen to lend more to rural areas through its various schemes.

As the country surges ahead, he said, there is need to focus on four things, quality, linkages for exports, capacity building, and support to achieve the vision of Vikshit Bharat.

Uttar Pradesh govt plans e-commerce booster shot for the MSME sector

To propel the growth of micro, small and medium enterprises (MSMEs), and enhance their competitiveness, the Uttar Pradesh (UP) government is planning to interconnect 155 industrial clusters with a dedicated e-commerce (e-com) platform.

This strategic move is expected to benefit over 50,000 industrial and manufacturing units of these clusters, administered by the UP State Industrial Development Authority (UPSIDA). The dedicated e-com portal is being developed by the UPSIDA, and will connect raw material suppliers, manufacturers, and finished goods vendors operating out of these 155 clusters.

Reducing reliance on external suppliers and cutting costs, the proposed e-marketplace can facilitate direct business-to business transactions, fostering trade and business alliances among the UP-based units.

“The e-market is a step towards realising the ‘Make in UP’ vision. By fostering a robust industrial

ecosystem, we aim to make UP a global manufacturing hub," UPSIDA Chief Executive Officer (CEO) Mayur Maheshwari said.

He noted that the e-marketplace, which is under the testing phase before launch, would help UP-based industries to save about Rs 20,000 crore in logistics and warehousing costs.

The project is also aimed at contributing to the flagship trillion-dollar economy agenda of the Yogi Adityanath-led UP government.

The UPSIDA's digital platform will enhance trade among the state industries, which is expected to catalyse the industrial growth, generate fresh jobs, and increase goods and services tax (GST) kitty by 7-10 per cent.

Also, by promoting local sourcing and reducing logistics costs, the e-market will strengthen UP's economy, streamline procurement processes, and improve transparency. The e-market will also take on board units engaged in packaging and marketing activities to offer a complete industrial value chain of services to clients.

At the same time, the UP government is increasing the industrial land bank, with a target to amass over 150,000 acres for industrial and infrastructure development. Of this, UP agencies already have 54,000 acres and the rest remains to be acquired.

Earlier, Chief Minister Yogi Adityanath directed the UP development authorities to expedite the process of land acquisition for allotment to private investors.

The land bank will be created by the UPSIDA, Noida, Greater Noida, the Yamuna Expressway Industrial Development Authority, and the Gorakhpur Industrial Development Authority.

SARU COPPER ALLOY SEMIS PVT.LTD.

Manufacturer & Exporters of:

Continuous Cast Cold Drawn Copper Alloy Rods & Bars in Sizes upto 160 mm to all National and International Specifications in Standard Length of 3 mt

Saru Nagar, Sardhana Road, Meerut- 250001
Ph. No.: 0121-2556279, 2554126, 2554160
Fax: 0121-2558402
Email: sales@sarucopper.com,
info@sarocopper.com
Website: www.sarucopper.com

Nipro PharmaPackaging is now Great Place to Work certified!!

Nipro PharmaPackaging India is part of Nipro Corporation Japan. Nipro, a global healthcare company employs over 35k colleagues and has a culture of high performance, customer focus, and employee engagement. This has led Nipro PharmaPackaging India to being awarded with the certificate of the Great Place to Work – Oct' 22 – Oct'23. In addition to the above achievement, Nipro PharmaPackaging India has now earned its recognition as being one of the top 50 "India's Best Workplaces in Manufacturing 2023".

Ashish Moghe, the Managing Director of Nipro in India, states, "Nipro's dedication to investing in its workforce is a key factor in its success. In 2022, Nipro PharmaPackaging India gathered further pace in the last year and crossed a few milestones. One such milestone was getting certified as a Great Place To Work! The Great Place to Work® Certification Program is the first step for an organization on its journey of building a High-Trust, High-Performance Culture™ and our organization has successfully accomplished this milestone.

To continue the same path of progress and development for us as individuals and as an organization we also enrolled ourselves for assessment for yet another prestigious certification, which is TOP 50India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. This year, 201 organizations in the Manufacturing sector undertook this assessment. All these organizations underwent a rigorous assessment. The results are finally out, and it gives me an immense amount of joy and pride to share that both plants of Nipro PharmaPackaging India (Meerut & Pune) HAVE WON THIS CERTIFICATION!!

I feel honoured to be a part of such a fantastic team. Looking forward to creating many more milestones"

"We are thrilled to receive the recognition as India's Best Workplaces in Manufacturing 2023. We are committed to fostering an environment of transparency, teamwork, and participation. Our organization promotes bonding among colleagues and encourages continuous improvement.Our team takes pride in working for a Great Place to Work certified company, and this recognition not only attracts top talent but also builds loyalty among our employees. The Trust Index study conducted by Great Place to Work provides valuable insights for us to improve as an organization. We strive to be an employer of choice and this recognition is a testament to our efforts.", states Mr. Juned Akhtar(General Manager- Human Resource, Nipro PharmaPackaging India Pvt. Ltd.